The Deputy Minister of Communications (Shri Raj Bahadur): Expenditure:—Rs. 1,122/10/3 per month.

Income:—Rs. 4.572/5/- per month, but this is not additional income since almost all the articles posted therein would otherwise have been consigned to the regular Post-Offices.

सेठ गोविन्द दास : यदि इस प्रकार का डाकखाना न खोला जाता तो जितनी आमदनी अभी हुई है वह पूरी की पूरी होती, या उस में कुछ कमी होती ?

श्री राज बहादुर : हो सकता है कि कुछ कम होती ।

सेठ गोविन्द दास : जैसे कि अभी माननीय मंत्री ने अंक बतलाये उन के अनुसार आमदनी ज्यादा हुई है तो क्या इस प्रकार के और डाकखाने खोलने का विचार है, और यदि है तो कहां ?

श्री राज बहादुर : यह हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर है । जब अच्छी होगी तो अधिक खोलने की इच्छा है, इस में कोई सन्देह नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस वर्ष और भी ऐसे डाकखाने खोले जावेंगे ?

श्री राज बहादुर : इस चीज़ को विचाराधीन ही माना जा सकता है ।

Shri Veeraswamy: May I know whether the mobile post office system has been introduced in other cities such as Madras, Bombay and Calcutta?

Shri Raj Bahadur: It has been introduced in Nagpur, Madras, Delhi and Cawnpore.

श्री जांगडे : क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी चलते फिरते डाकखाने चालू करने का कोई विचार किया गया है ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये हमने एक प्रयोग किया था, किन्तु वह सफल नहीं हो सका और आशा यह की जाती है कि इस प्रयोग को एक बार फिर किया जाय । अगर वह सफल होगा तो इस को चालू किया जावेगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : सन् १९५२-५३ में मोबाइल पोस्ट आफिसेज की संख्या कितनी बढ़ने वाली है और उस के लिये कितना अधिक खर्चा होगा ?

Mr. Speaker: It is off the mark so far as the principal question is concerned. The principal question is about the mobile post offices. Next question.

RE-GROUPING OF RAILWAYS

*2298. **Shri Balmiki:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the annual economy effected by the formation of Northern, North Eastern and Eastern Zones in Railways; and

(b) the number of railway employees who have to move from the place of their duty before formation of these zones to other places?

The Minister of Railways and Transport (Shri L. B. Shastri): (a) As the Northern, North Eastern and Eastern Railways started functioning as complete systems only with effect from May 15, 1952, it is too early to assess the full extent of the economy secured as a result of the formation of these zones.

(b) 108 (20 officers and 88 class III and IV all volunteers).

श्री बाल्मीकी : इस प्रकार जो बचत होने की सम्भावना है, उस बचत से रेलवे के छोटे कर्मचारियों के स्तर को उठाने के लिये सरकार कहां तक खर्च करने का विचार रखती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : पहले तो क्या बचत होगी उस का ही अन्दाज़ा नहीं है । जब उस का अन्दाज़ा हो जाये तब इस बात पर विचार होगा ।

Shri A. C. Guha: May I know if there will be any expenditure incurred for the construction of new offices and for providing residental accommodation in Gorakhpur and Delhi for these two offices?

Shri L. B. Shastri: We may have to build in a small place. I do not think we will have to spend a large sum.

Shri A. C. Guha: May I know if a large number of staff at the Calcutta headquarters for the E. I. and B. N. Railways would be surplus in view of the fact that about or more than half of the E. I. R's route mileage has gone out of the eastern section?

Shri L. B. Shastri: Yes. There might be some surplus in staff.

Shri A. C. Guha: May I know how the Government intend to utilize them?

Mr. Speaker: I think this question about the zones has been discussed very much.

Shri A. C. Guha: That was only about the arrangement of the zones but not about the staff. May I know how the Government intend to utilise the staff and what will be the surplus there?

Shri L. B. Shastri: We have to utilize them because Government have given assurances to the staff that they will not be retrenched or transferred without their consent.

Shri B. K. Das: May I know how many employees have been transferred from Calcutta?

Shri L. B. Shastri: I shall require notice for that. I have stated that only 108 is the total number of officers and workers transferred.

श्री पी० एन० राजभोज : रिग्रुपिंग के कारण कर्मचारियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है, क्या यह सच है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, बढ़ी नहीं घटने की उम्मीद है ।

श्री बालमोकी : किन सुधारों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस योजना को अपने हाथ म लिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यह तो सही है, हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिस में इस चीज़ को ध्यान में न रखा जाय ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

* २२९९. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसंधान तथा परीक्षणों के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को किसानों के लाभार्थ विक्रय, प्रदर्शन या बिना मूल्य वितरण या नमूने का काम देने के लिये अब तक विभिन्न राज्यों में भेजा जा चुका है ?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Shri Satish Chandra): The Indian Council of Agricultural Research maintains no research station of its own. It promotes and influences research in the country by financing research schemes in conjunction with State Governments who are primarily responsible for exploiting approved results of research. The Council assists them in giving publicity to the results of research and their application. The Council also publishes results obtained through its schemes in its scientific publications and in non-technical language in its popular monthly journals 'Indian Farming' (English) and 'Kheti' (Hindi) which are widely distributed and also supplied to the Library of Parliament.

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने गन्ने की रैड राट बीमारी के लिये जो एक दवाई निकाली है और खेती के लिये, विशेषकर चावल की खेती के कीड़े को नष्ट करने के लिये जो दवाइयां निकाली हैं, उन दवाइयों को अधिक मात्रा में किसानों तक पहुंचाने के लिये कोई कारखाना जारी करने का विचार किया है ?

श्री सतीश चन्द्र: इस के लिय मझे नोटिस चाहिय लेकिन मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि जिन दवाइयों की, गैनेकसीन वगैरा की ज़रूरत होती है उन को काफी मात्रा में किसानों तक पहुंचाने की कोशिश स्टेट ग्रवर्नमेंट्स के मार्फत की जाती है।

श्री जांगड़े : क्या म जान सकता हूं कि गेहूं की खेती में जो रस्ट (rust) वगैरह की बीमारी को रोकने के लिये सर-